कैबिनेट के नए फैसले

लेखक - उदित मिश्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

24 अक्टूबर, 2019

"बुधवार को सरकार द्वारा दूरसंचार, कृषि और पेट्रोलियम क्षेत्रों पर लिए गए फैसले से क्या संकेत मिलता है? इस आलेख में हम समझेंगे कि सरकार की हालिया घोषणाओं का संदर्भ क्या है और इसके क्या मायने हैं?"

बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ प्रमुख आर्थिक नीति निर्णयों की घोषणा की जिसमें से पहला, दो घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों - भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) - के लिए विलय और पुनरुत्थान पैकेज था, दूसरा रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि थी और तीसरा पेट्रोल और डीज़ल के विपणन के लिए इसकी व्यवस्था को उदार बनाना था।

एमटीएनएल-बीएसएनएल विलय

संदर्भ: पिछले कुछ समय से यह तर्क दिया जा रहा था कि सरकार को दूरसंचार क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि इसकी फर्मों - बीएसएनएल और एमटीएनएल - को निजी क्षेत्र के कारण लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले चार वर्षों में, एमटीएनएल और बीएसएनएल के राजस्व में क्रमश: 30% और 40% की गिरावट आई है। पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में, दोनों कंपनियों ने क्रमश: 14,000 करोड़ रुपये और 3,388 करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान की सूचना दी है। संचयी नुकसान बहुत अधिक हैं। ये नुकसान अनिवार्य रूप से करदाताओं पर बोझ बढ़ा रहे हैं।

कंपनियों की बड़ी कर्मचारी ताकत (बीएसएनएल के पास 1.7 लाख कर्मचारी हैं) ने उन्हें घाटे के मामले में और अधिक अस्थिर बना दिया है। इसलिए, सरकार दो फर्मों का विलय करने और 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लाने का फैसला किया है। वीआरएस की लागत 17,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।

सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की मौजूदा संपत्ति का मुद्रीकरण करके धन जुटाने का भी फैसला किया है और इस मार्ग से 38,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। विलय किया गया बॉन्ड फ्लोट करेगा (यानी बॉन्ड बेचेंगे और बदले में पैसा मिलेगा) जिस पर सरकार की गारंटी होगी - इस मार्ग से 15,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

नए प्राप्त धन का उपयोग विलय की गई इकाइयों के ऋणों को कम करने के लिए किया जाएगा और इसे 4जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किया जाएगा ताकि यह बेहतर क्षेत्र में शेष क्षेत्र के इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

विश्लेषण: बीएसएनएल और एमटीएनएल को रणनीतिक संपत्ति के रूप में मानने और उन्हें पुनर्जीवित करने की बात को दूरसंचार क्षेत्र में चल रहे संकट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहाँ निजी खिलाड़ियों के थोक - जैसे टाटा टेलीसर्विसेज़, आरकॉम, एयरसेल, टेलीनॉर और वीडियोकॉन - ने हाल के वर्षों में दुकान बंद कर दी है। संक्षेप में, अब सिर्फ तीन कंपनियाँ हैं - सभी निजी - जो जीवित हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके भी राजस्व में कमी देखी गई है और इनके ऋण भी लाखों करोड़ों में बढ़े हैं।

अब सवाल उठता है कि क्या विलय की गई इकाइयाँ सरकार के समर्थन की बदौलत कम और कमज़ोर प्रतिस्पर्धा को बेहतर ढंग से संभाल पाएगी या नहीं? या क्या यह निजी क्षेत्रों के लिए बेहतर समय में संघर्ष करेगा? हालाँकि, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है।

रबी एमएसपी में वृद्धि

संदर्भ: 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख सफलताओं में से एक सामान्य मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करने की क्षमता है जो 2013 के अंत में दोहरे अंकों के उच्च स्तर पर पहुँच गई थी। जबकि इस गिरावट के लिए कई कारक ज़िम्मेदार थे, जैसे - 2014 और 2015 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट - सरकार द्वारा किसी भी वर्ष में बड़ी मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का नीतिगत निर्णय काफी महत्त्वपूर्ण साबित हुआ था। एमएसपी भारत में फसल के पैटर्न और समग्र उत्पादन के सबसे महत्त्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है क्योंकि ये कई वस्तुओं के साथ खेत की कीमतों के लिए बेंचमार्क का संकेत देते हैं।

नवीनतम वृद्धि गेहूँ के लिए 85 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि मुख्य रबी फसल है, यह बढ़ कर एमएसपी को 1,925 रुपये प्रति क्विंटल पर ले जाती है। यह मोटे तौर पर अपनी सीमा के भीतर है (वास्तव में, थोड़ा कम ही है) वार्षिक एमएसपी के साथ गेहूँ में 2014 के बाद से वृद्धि हुई है (जब यह 1,450 रुपये प्रति क्विंटल था)।

विश्लेषण: उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एमएसपी में मामूली वृद्धि एक स्वागत योग्य संकेत होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, सितंबर में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति 3% से 4.7% तक बढ़ गई। चूँकि खाद्य पदार्थों की खुदरा मुद्रास्फीति 54% से अधिक है, इसलिए सम्पूर्ण मुद्रास्फीति भी 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई। इसलिए, मामूली एमएसपी वृद्धि यह सुझाव देता है कि भोजन की कीमतें शायद बहुत अधिक नहीं बढ़ेंगी।

हालाँकि, इस मामले में किसानों की राय बहुत अलग है। कृषि मजदूरी (farm wages) में ठहराव और ग्रामीण माँग में समग्र गिरावट के लिए मामूली वृद्धि को दोषी ठहराया गया है। इस मामले पर सबसे हालिया आलोचना 2019 अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी द्वारा की गयी, जिन्होंने उदास ग्रामीण माँग के कारण एमएसपी को कम करने का संकेत दिया।

अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को ग्रामीण आय और माँग को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को एक बड़ी मात्रा में बढ़ाना चाहिए? यदि इसका जवाब हाँ है, तो ऐसा करने से बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के दबाव का खतरा बढ़ जाएगा जो आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती के चक्र को उलटने के लिए मजबूर कर सकता है।

ईंधन रिटेल को उदार बनाना

संदर्भ: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा डीज़ल और पेट्रोल जैसे परिवहन ईंधन की खुदरा बिक्री लगभग पूरी तरह से हावी है। कुछ निजी खिलाड़ी भी हैं जैसे - रिलायंस, एस्सार और शेल आदि - लेकिन मई 2019 तक देश के 64,703 रिटेल आउटलेट्स में से 7,000 से कम इनके थे।

हालाँकि, सरकार ने अब 'बाज़ार परिवहन ईंधन के हेतु प्राधिकरण देने के लिए दिशा-निर्देशों को बदलकर इस व्यवस्था को उदार बनाने का फैसला किया है, जिसे 2002 के बाद से नहीं किया गया था। संक्षेप में, नए नियम निजी (विदेशी सहित) खिलाड़ियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करते हैं, ताकि ये ईंधन रिटेल बिक्री के लिए बाजार में प्रवेश कर सके। उदाहरण के लिए, नए प्रवेशकर्ताओं को 2,000 करोड़ रुपये की वर्तमान आवश्यकता के मुकाबले महज 250 करोड़ रुपये की न्यूनतम शुद्ध मूल्य की आवश्यकता होगी। गैर-तेल कंपनियाँ भी अब निवेश कर सकती हैं। यह 'प्रमुख सुधार' 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा।

विश्लेषण: भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए, जो तेजी से बढ़ने और अधिक रोज़गार पैदा करने और प्रवेश बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रहा है, हमे उसका स्वागत करना चाहिए। विदेशी कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई उपस्थिति, रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने और अधिक खुदरा दुकानों, बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग और अधिक प्रतिस्पर्धा के साथ उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार की संभावना है।

नए मानदंडों का एक दिलचस्प पहलू यह है कि पारंपरिक ईंधन के अलावा, अधिकृत संस्थाओं को कम से कम एक नई पीढ़ी के वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, एलएनजी, जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग आदि के लिए तीन साल के भीतर सुविधाएँ स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए:-

1. सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) का विलय कर दिया है।
2. वर्तमान में खाद्य पदार्थों की खुदरा मुद्रास्फीति 54% से अधिक है, इसलिए संपूर्ण मुद्रास्फीति भी 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।
3. बाजार परिवहन ईंधन के लिए प्राधिकरण देने वाले दिशा-निर्देशों को बदल दिया गया है एवं यह बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा।

कूट:-

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Considering the following statements, identify the true statement: -

1. The government has merged Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL).
2. Currently, the retail inflation of food items is more than 54% so the overall inflation has also reached a 14, months high.
3. The guidelines giving authorization for market transport fuels have been changed and this change will give a boost to 'Ease of Doing Business.'

Code:-

(a) 1 and 2 (b) 1 and 3

(c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत की वर्तमान दूरसंचार व्यवस्था में सरकार की ओर से बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का विलय करना तथा पुनरुत्थान पैकेज दिया जाना तार्किक कदम होगा।' अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

'In India's current telecommunication system, merging BSNL and MTNL and giving revival package will prove a logical step by the government.' Give an argument in favor of your opinion. (250 words)

(250 words)

नोट : 23 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।